

प्रेषक

सी० भारकर,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संवा में

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि०  
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2.

देहरादून दिनांक: 20 मार्च, 2008

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में मनेरी भाली-1। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० को ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक निदेशक (वित्त) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० की पत्र संख्या 117/1/JVNL/D(FY)MB-II/PDF, दिनांक 14.02.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनेरी भाली-1। परियोजना के निर्माण हेतु ऋण के रूप में रु० 90,00,00,000.00 (रु० नब्बे करोड़ मात्र) की धनराशि संग्रह की०एम०-15 अनुसार अनुदानान्तर्गत विभिन्न लेखाशीर्षकों में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनिर्माण के माध्यम से व्यय करने के लिये प्राप्त निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृति की जा रही धनराशि केवल उक्त परियोजना के निर्माण हेतु ही व्यय की जायेगी।
- 2- स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहरताक्षर उपरान्त कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
- 3- व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक स्टोर वर्कज तथा शासन के मितवाचता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय सी०जी०एस० एण्ड सी० अथवा टेंडर/कुटेशन विधियों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
- 4- कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगमन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 5- करायें जाने वाले कार्यों की कम्प्यूटरोक्त इन्वेन्ट्री तैयार की जायेगी जिसकी सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 6- आवश्यक सामग्री का क्रय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7- इस ऋण पर भी ब्याज की दर 9.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी वार्षिक 10 समान किश्तों में होगी, जिसकी प्रथम किश्त माह जुलाई, 2008 से प्रारम्भ होगी। ब्याज की धनराशि का त्रैमासिक भुगतान किया जायेगा।
- 8- प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।
- 9- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० जब भी ऋण वापसी की किश्तों एवं ब्याज का भुगतान करे महालेखाकार कार्यालय एवं शासन के ऊर्जा सैल को निम्न किन्दुओं पर सूचना भेजें:-  
1- कोषागार का नाम, 2- चालान सं०, 3- जमा धनराशि, किश्त ब्याज, 4- शासनादेश संख्या और एस०एल० आर० का संदर्भ, 5- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

6

- 10- उज्जयिनीति जो दिये जाने वाले ऋण का लेखा शासन के ऊर्जा सैल द्वारा भी रखा जायेगा।
  - 11- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा ले।
  - 12- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब वह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।
  - 13- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31/03/2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।
  - 14- अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
  - 15- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-उपयुक्त के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801-विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-जल विद्युत उत्पादन-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-06-जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेडीएनएस में निवेश-00-30-निवेश/ऋण के नामों डाला जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के जरासकीय संख्या 313/XXVII(2)/2008, दिनांक 20 मार्च 2008 द्वारा प्राप्त उनकी महमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

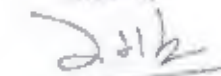
(सी० भास्कर)  
अपर सचिव

संख्या: 775/1(2)/2008-04(8)/13/07, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के सज्ञान में लाने हेतु।
- 5- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 6- श्री एन०एम० पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- प्रभारी, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(एम०एम० सेमवाल)  
अनु सचिव

$$T = \frac{1}{2} \frac{d^2 \mathcal{L}}{d\alpha^2} \Big|_{\alpha=0}$$
[illegible]

प्रमाणित किया गया है कि पुनर्निर्माण के इरादे से निर्माण के लिए 150.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया है।



समानाधिकार शासन  
विभाग-2  
पत्रांक: 11/21/2008-04(8)/13/04, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008

सुनिश्चितता स्वीकृति

(डी. एच. एच. जी. जी.)  
उप-सचिव, विभाग

संख्या:

महाराष्ट्र शासन  
उप-सचिव, विभाग

775  
11/21/2008-04(8)/13/04, दिनांक 25 अक्टूबर, 2008

सुनिश्चितता स्वीकृति को सुनिश्चित रूप से उपस्थित करवावे। (ग. प्रमाण)

- 1- वार्षिक कार्यावली, देखावे।
- 2- विभाग-2

25/10/08

(डी. एच. एच. जी. जी.)  
उप-सचिव, विभाग